सं ओं.वि./एफ डी./133-85/37715.—चूिक हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. फरीदाबाद फाऊंडरी प्लाट मं 306, सैक्टर 24, के श्रमिक श्री राम दास तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीदोगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हैतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खाड (गा द्वारा प्रदान की गई शिवतयों का प्रयोग करते हुये, हिरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 5415-3-अम-58/1 विवाद 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1955 द्वारा उन्त धिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय फरीदाबाद को विवाद प्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय एवं पंचाद तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—*

क्या श्री राम दास की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो.वि/एफ.डी./153-85/37722.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. फरीदाबाद फाऊंडरी प्लाट नं. 306, सक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री दिनेश तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, अौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रवान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-8म/68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495/जो. अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तंन मास में देने हैंतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :=-

क्या श्री दिनेश की सेवाग्रों का समापन न्यायोजित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? दिनांक 17 सितम्बर, 1985

्रं सं. भ्रों.वि./एफ.डी./207-85/38302.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं एस्कोर्ट्स लि०, प्लाट नं० 2, ट्रैक्टर डिविजन, फरीदाबाद के श्रमिक श्री चैन सुख तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत् निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, श्रव, श्रौद्योगिक विवाद श्रिष्टिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हिरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिष्टिस्चना सं. 5415-3-श्रीम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए श्रिष्टिस्चना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त श्रिष्टिस्चना की धारा 7 के श्रधीन गटित श्रम ग्यायालय, फरीदाबाद, को विवादशस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्वन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हैत् निर्दिष्ट करते हैं, जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादशस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत श्रथवा सम्बन्धित मामला है;

क्या श्री चैन सुख की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदिनहीं, तो वह किस राहत का हकदार है? सं.श्रो.वि./एफ.डी./201-85/38309.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में. इंडो पाल फूड प्रोसेसिंग मशीनरी प्राठलिंठ, प्लाट नंठ 28, सैक्टर-27, फरीदाबाद, के श्रीमक श्री तीर्थ राज तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रौद्योगिक विवाद है;

भीर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत् निर्दिष्ट करना वाछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान का गई शिवतयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादअस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने के हेतु निदिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादअस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथया संबंधित मामला है:—

क्या श्री तीर्व राज की सेवाझों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?